नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 091
दि. 02.01.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

ठाकरे के गढ़ वर्ली से महायुति का विशाल शक्ति प्रदर्शन, 3 जनवरी को मुंबई नगर चुनाव का जोरदार चुनावी शंखनाद

(जीएनएस)। मुंबई। लंबे समय तक चले सीटों के बंटवारे, अंदरूनी खींचतान और रणनीतिक बैठकों के दौर के बाद अब महायुति ने मुंबई सहित राज्य की सभी नगर निगमों के चुनावी रण में खुलकर उतरने का फैसला कर लिया है। इसी क्रम में 3 जनवरी 2026 को मुंबई के वर्ली स्थित एनएससीआई डोम में आयोजित होने वाली भव्य जनसभा को महायुति अपने चुनावी शंखनाद के रूप में देख रही है। शाम छह बजे शुरू होने वाली इस सभा के जरिए न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र की 29 नगरपालिकाओं के लिए प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस सभा में मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहेंगे और जनता को आगामी चुनावों के लिए महायुति का संदेश देंगे। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, इस सभा का स्थान और समय दोनों ही बेहद सोच-समझकर तय किए गए हैं। वर्ली को लंबे समय से ठाकरे परिवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है। शिवसेना की राजनीति की कई ऐतिहासिक सभाओं और आंदोलनों का साक्षी रहा यह इलाका उद्धव ठाकरे गुट के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखता है। ऐसे में महायुति द्वारा यहीं से चुनावी अभियान की शुरुआत करना सीधे तौर पर ठाकरे गुट को चुनौती देने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। संदेश साफ है कि महायुति अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मुद्रा में चुनाव मैदान में उतरने जा रही है।

महायुति के भीतर हाल के दिनों में सीटों के बंटवारे को लेकर जो असहजता देखने को मिली थी, उसे पीछे छोड़कर अब गठबंधन एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहता है। वर्ली की यह सभा उसी एकता का सार्वजनिक मंच बनने वाली है। भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और अन्य सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता एक ही मंच पर दिखाई देंगे। यह दृश्य कार्यकर्ताओं और मतदाताओं दोनों के लिए यह संकेत होगा कि तमाम मतभेदों के बावजूद गठबंधन चुनावी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। माना जा रहा है कि इस मंच से महायुति नेतृत्व यह दिखाने की कोशिश करेगा कि गठबंधन न सिर्फ स्थिर है, बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र के विकास को लेकर उसके पास एक साझा और स्पष्ट रोडमैप भी है।

इस सभा का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ठाकरे गुट ने अपनी संयुक्त प्रचार बैठकों की शुरुआत 5 जनवरी से करने की घोषणा की है। ऐसे में महायुति द्वारा दो दिन पहले ही वर्ली से मोर्चा खोल देना मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की कोशिश माना जा रहा है। चुनावी राजनीति में समय और प्रतीक दोनों का विशेष महत्व होता है, और महायुति इस पहल के जरिए यह संदेश देना चाहती है कि वह चुनावी एजेंडे और विमर्श की दिशा तय करने में पहल करना चाहती है, न कि प्रतिक्रिया देना। नगर निगम चुनावों की समय-सारिणी को देखें तो यह सभा और भी अहम हो जाती है। राज्य की 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को मतदान होना है और 16 जनवरी को नतीजे सामने आएंगे। यानी प्रचार के लिए महज कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में वर्ली की यह बैठक अगले करीब 12 दिनों के सघन प्रचार अभियान की दिशा और स्वर तय करेगी। सूत्रों के मुताबिक, इस मंच से मुंबई के बुनियादी ढांचे, परिवहन, आवास, स्वच्छता, झुग्गी पुनर्विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर महायुति अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर सकती है। मराठी अस्मिता, स्थानीय नेतृत्व और उम्मीदवार चयन जैसे संवेदनशील विषयों पर भी गठबंधन अपनी स्थिति को मजबूती से रखने की कोशिश करेगा।

इस जनसभा का एक बड़ा उद्देश्य कार्यकर्ताओं में जोश और आत्मविश्वास भरना भी है। चुनावी मैदान में संगठन की ताकत तभी दिखती है जब जमीनी कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ सक्रिय हों। महायुति नेतृत्व इस सभा के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाना चाहता है कि गठबंधन की कमान मजबूत हाथों में है और चुनावी लड़ाई पूरी रणनीति और अनुशासन के साथ लड़ी जाएगी। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के इस सभा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे यह आयोजन शक्ति प्रदर्शन का रूप ले सकता है।

वर्ली डोम की इस शुरुआत के बाद महायुति का प्रचार अभियान और तेज होने वाला है। सूत्रों के अनुसार, इसके तुरंत बाद मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में विभागवार बैठकें, रोड शो, जनसंपर्क अभियान और उम्मीदवारों के समर्थन में सभाओं का सिलसिला शुरू होगा। हर क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रचार की रणनीति तैयार की गई है, ताकि मतदाताओं तक सीधे और प्रभावी तरीके से संदेश पहुंचाया जा सके।

कुल मिलाकर, 3 जनवरी की वर्ली सभा महज एक चुनावी बैठक नहीं बल्कि महायुति की राजनीतिक मंशा और आत्मविश्वास का सार्वजनिक प्रदर्शन होगी। ठाकरे के गढ़ से चुनावी शंखनाद कर महायुति यह स्पष्ट करना चाहती है कि मुंबई की सियासत में अब मुकाबला सीधा, तीखा और निर्णायक होने वाला है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस शक्ति प्रदर्शन का असर मतदाताओं के मन पर कितना गहरा पड़ता है और मुंबई की राजनीति किस नई दिशा में आगे बढ़ती है।

सौगात से शुरू होगी लंबी दूरी की रेल यात्रा की नई क्रांति, गुवाहाटी कोलकाता रूट पर दौड़ेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

(जीएनएस)। नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत के साथ ही भारतीय रेलवे ने देश को एक ऐतिहासिक सौगात दी है। रेल मंत्री ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह अत्याधुनिक और सेमी हाई-स्पीड ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी, जिससे पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के बीच रेल संपर्क को नई मजबूती मिलेगी। लंबे समय से जिस हाईटेक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का इंतजार किया जा रहा था, वह अब हकीकत बनने जा रही है। रेलवे का मानना है कि इस ट्रेन के शुरू होने से न सिर्फ यात्रा का समय कम होगा, बल्कि लंबी दूरी का सफर पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक और आधुनिक हो जाएगा। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी यह परियोजना असम और पश्चिम बंगाल के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। रेल मंत्रालय के अनुसार इस ऐतिहासिक ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री 17 या 18 जनवरी को इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। रेलवे की ओर से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और जैसे ही उद्घाटन की अंतिम तारीख तय होगी, टिकट बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को विशेष रूप से लंबी दूरी की रात की यात्राओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और आराम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आम यात्रियों को किफायती सफर का लाभ देने के लिए इसमें थर्ड एसी कोचों की संख्या ज्यादा रखी गई है, ताकि मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोग भी कम खर्च में आधुनिक ट्रेन का अनुभव कर सकें।

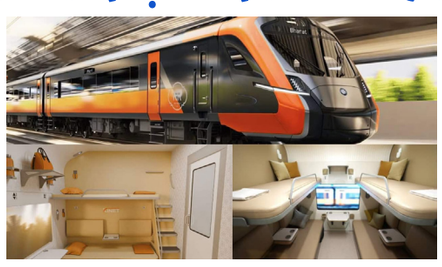

रेल मंत्री ने बताया कि यह ट्रेन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई है और हाल ही में इसका अंतिम हाई-स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। यह ट्रायल कोटा–नागदा सेक्शन पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में हुआ, जहां ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। इस सफल परीक्षण के बाद वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के व्यावसायिक संचालन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह ट्रेन तकनीक, सुरक्षा और गति के मामले में भारतीय रेलवे के लिए एक नया मानक स्थापित करेगी।

इस ट्रेन को खास बनाने के लिए इसमें केवल तकनीकी सुविधाओं ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों को क्षेत्रीय स्वाद का अनुभव कराने की तैयारी की गई है। गुवाहाटी से चलने वाली ट्रेन में असम के पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे, जबकि कोलकाता से रवाना होने वाली ट्रेन में बंगाल के प्रसिद्ध खानपान को शामिल किया जाएगा। रेलवे का मानना है कि इससे यात्रियों का सफर सिर्फ आरामदायक ही नहीं रहेगा, बल्कि वे रास्ते में ही अलग-अलग राज्यों की संस्कृति और स्वाद से भी रूबरू हो सकेंगे। गुवाहाटी–कोलकाता वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कुल 16 कोच की होगी। इनमें 11 थर्ड एसी, चार सेकंड एसी और एक फर्स्ट एसी कोच शामिल रहेगा। इस ट्रेन में एक बार में 823 यात्री सफर कर सकेंगे। ट्रेन में आधुनिक और मुलायम स्लीपर बर्थ, दो कोचों के बीच ऑटोमेटिक दरवाजे और वेस्टीब्यूल, बेहतर सस्पेंशन सिस्टम और कम शोर वाली तकनीक दी गई है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा थकान रहित और सुकून भरी हो सके। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के साथ यह ट्रेन समय की बचत भी करेगी।

रेलवे ने इस ट्रेन के संभावित किराए की जानकारी भी साझा की है। गुवाहाटी से कोलकाता के बीच थर्ड एसी का किराया करीब 2,300 रुपये, सेकंड एसी का लगभग 3,000 रुपये और फर्स्ट एसी का किराया करीब 3,600 रुपये रखा जा सकता है। रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि किराया इस तरह तय किया गया है कि यह हवाई यात्रा के मुकाबले काफी सस्ता हो। वर्तमान में गुवाहाटी से हावड़ा के बीच हवाई टिकट का किराया छह से आठ हजार रुपये तक पहुंच जाता है, जबकि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आम यात्रियों को कम खर्च में तेज और आरामदायक विकल्प देगी।

रेल मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का नेटवर्क आने वाले समय में तेजी से बढ़ाया जाएगा। अगले छह महीनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में आठ नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने की योजना है, जबकि साल के अंत तक इनकी संख्या बढ़कर 12 तक पहुंच सकती है।

जल्द ही पेट्रोल पंपों की बदलेगी सूरत, आधुनिक ऊर्जा स्टेशनों में होंगे तब्दील

(जीएनएस)। नई दिल्ली। आने वाले वर्षों में देशभर के पेट्रोल पंपों की तस्वीर पूरी तरह बदलने जा रही है। अब ये पंप केवल पेट्रोल-डीजल भरवाने की जगह नहीं रहेंगे, बल्कि आधुनिक और बहु-उद्देशीय ऊर्जा स्टेशनों के रूप में विकसित होंगे, जहां एक ही परिसर में पारंपरिक ईंधन के साथ-साथ जैव ईंधन, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने इस दिशा में बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने 2028-29 तक देश में चार हजार ऐसे आधुनिक ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है, जिन्हें भविष्य की परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा।

तेल कंपनियों का मानना है कि वाहन तकनीक में तेजी से हो रहे बदलाव और वैकल्पिक ईंधन की बढ़ती मांग को देखते हुए पेट्रोल पंपों का स्वरूप बदलना समय की जरूरत है। इसी रणनीति के तहत वर्ष 2026 तक करीब ढाई हजार ऊर्जा स्टेशन तैयार करने की योजना बनाई गई है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इन स्टेशनों को एकीकृत मोबिलिटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां निजी वाहन चालकों के साथ-साथ व्यावसायिक वाहनों को भी हर तरह की ऊर्जा और सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जा रहा है, जहां पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो और भविष्य में विस्तार की पूरी गुंजाइश बनी रहे, ताकि बढ़ती जरूरतों के अनुसार अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ी जा सकें।

डिजिटल इंडिया अभियान के तहत पेट्रोल पंपों को तकनीकी रूप से भी अधिक सक्षम बनाया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 2026 तक देश के अधिकतर पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों पर प्वाइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीनें लगाने का लक्ष्य रखा है, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिल सके और ग्राहकों को नकद लेनदेन की झंझट से मुक्ति मिले। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में जहां लगभग एक लाख पीओएस मशीनें ईंधन स्टेशनों पर मौजूद थीं, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर ढाई लाख तक पहुंच गई है। आने वाले समय में यूपीआई, कार्ड और अन्य डिजिटल माध्यमों से भुगतान को और अधिक सहज और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जाएगा।

इसके साथ ही पेट्रोल पंपों को यात्रियों के लिए सुविधाजनक ठहराव केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग सभी खुदरा ईंधन स्टेशनों पर शौचालय की सुविधा सुनिश्चित की जा चुकी है। इनमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं और साफ-सफाई के मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि वर्ष 2026 में दिव्यांगजनों के अनुकूल शौचालयों के निर्माण पर विशेष जोर रहेगा, ताकि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले हर वर्ग के लोगों को सुविधा मिल सके। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने ट्रक चालकों के लिए आराम और विश्राम की व्यवस्था को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। सरकारी अध्ययनों में सामने आया है कि हाइवे पर होने वाली कई दुर्घटनाओं का कारण ट्रक चालकों को पर्याप्त आराम न मिल पाना है। इसी समस्या के समाधान के लिए देश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर वातानुकूलित आराम-घरों का निर्माण किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष देशभर के विभिन्न हाइवे पर ट्रक ड्राइवरों के लिए 500 से अधिक एसी आराम-घर बनाने की योजना है, जहां उन्हें आराम करने, भोजन करने और बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे न केवल सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है, बल्कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर पेट्रोल पंपों को आधुनिक ऊर्जा स्टेशनों में बदलने की यह पहल देश की बदलती परिवहन व्यवस्था, पर्यावरणीय जरूरतों और यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। आने वाले समय में जब वाहन चालक किसी पेट्रोल पंप पर रुकेंगे, तो उन्हें ईंधन भरवाने के साथ-साथ चार्जिंग, डिजिटल भुगतान, स्वच्छ शौचालय और आराम की सुविधाएं भी एक ही स्थान पर मिलेंगी।

एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला वायुसेना उपप्रमुख का पदभार, चार दशक के अनुभव के साथ मिली देश की हवाई सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना को नया नेतृत्व मिल गया है। एयर मार्शल नागेश कपूर ने गुरुवार को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के उपप्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। इस महत्वपूर्ण नियुक्ति के साथ ही देश की हवाई सुरक्षा, रणनीतिक तैयारियों और भविष्य की सैन्य योजनाओं में उनके अनुभव और नेतृत्व की अहम भूमिका मानी जा रही है। एयर मार्शल कपूर इससे पहले दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जहां उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों, प्रशिक्षण और सीमावर्ती क्षेत्रों में वायुसेना की क्षमता को मजबूती देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एयर मार्शल नागेश कपूर ने अपने पदभार ग्रहण से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वायु भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो भारतीय वायुसेना की परंपराओं और अनुशासन का प्रतीक है। इस मौके पर वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी और शीर्ष सैन्य नेतृत्व मौजूद रहा। एयर मार्शल कपूर ने एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लिया है, जिन्होंने लगभग चार दशकों तक भारतीय वायुसेना में सेवाएं देने के बाद बुधवार को सेवानिवृत्ति ग्रहण की।

भारतीय वायुसेना की ओर से सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी जानकारी में बताया गया कि एयर मार्शल नागेश कपूर का सैन्य करियर बेहद समृद्ध और प्रेरणादायक रहा है। उन्हें दिसंबर 1986 में फ्लाइंग ब्रांच में कमीशन प्राप्त हुआ था। अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों और प्रशिक्षक विमानों को उड़ाने का व्यापक अनुभव हासिल किया है।

धूम्रपान पर सरकार की सख्ती, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर बदली कर व्यवस्था, 1 फरवरी 2026 से जेब पर पड़ेगा सीधा असर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और राजस्व संतुलन को ध्यान में रखते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर कर ढांचे में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा 40 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त अब तंबाकू उत्पादों पर नया उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा, जो 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। सरकार के इस फैसले से सिगरेट की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और धूम्रपान को हतोत्साहित करने की नीति को बल मिलेगा।

नई कर व्यवस्था के तहत सिगरेट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क उसकी लंबाई और श्रेणी के आधार पर तय किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रति 1,000 सिगरेट पर यह अतिरिक्त शुल्क 2,050 रुपये से लेकर 8,500 रुपये तक होगा। इसका अर्थ यह है कि जितनी लंबी और प्रीमियम श्रेणी की सिगरेट होगी, उस पर टैक्स का बोझ उतना ही ज्यादा पड़ेगा। इस वर्गीकरण के जरिए सरकार ने प्रीमियम और सामान्य सिगरेट के बीच कर संरचना को और स्पष्ट कर दिया है, ताकि उच्च श्रेणी के तंबाकू उत्पादों की खपत को और अधिक हतोत्साहित किया जा सके।

महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह नया शुल्क किसी भी तरह से जीएसटी का स्थान नहीं लेगा, बल्कि यह 40 प्रतिशत जीएसटी के ऊपर अतिरिक्त रूप से लगाया जाएगा। यानी उपभोक्ताओं को अब सिगरेट और तंबाकू उत्पाद खरीदने पर दो स्तरों पर कर चुकाना होगा। हाल ही में संसद से पारित केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 के जरिए इस बदलाव को कानूनी मान्यता दी गई है। सरकार का कहना है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की अवधि समाप्त होने के बाद जो राजस्व अंतर पैदा हुआ है, उसकी भरपाई के लिए यह कदम जरूरी था।

संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि इस नए उत्पाद शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कोई उपकर नहीं है, बल्कि उत्पाद शुल्क है, जिसे विभाजित किए जाने वाले कोष में शामिल किया जाएगा। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, इस राजस्व का 41 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को मिलेगा। इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है, खासकर ऐसे समय में जब स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि जीएसटी लागू होने से पहले भी तंबाकू उत्पादों पर हर साल करों में वृद्धि की जाती रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में तंबाकू करों को या तो महंगाई के साथ जोड़ा जाता है या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद्देनजर समय-समय पर बढ़ाया जाता है। भारत में भी इस वृद्धि का मूल उद्देश्य केवल राजस्व जुटाना नहीं है, बल्कि लोगों को तंबाकू की लत से दूर रखना और धूम्रपान से होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण पाना है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि तंबाकू उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से खासकर युवा वर्ग और पहली बार धूम्रपान करने वालों पर असर पड़ता है। महंगी सिगरेट उनकी पहुंच से बाहर होती है, जिससे खपत में कमी आने की संभावना रहती है। सरकार पहले ही सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी, विज्ञापन प्रतिबंध और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक जैसे कई कदम उठा चुकी है। अब टैक्स बढ़ोतरी को उसी कड़ी का अगला चरण माना जा रहा है। हालांकि, तंबाकू उद्योग से जुड़े संगठनों ने इस फैसले पर चिंता जताई है और आशंका व्यक्त की है कि इससे अवैध सिगरेट और तस्करी को बढ़ावा मिल सकता है। इसके बावजूद सरकार का रुख साफ है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और दीर्घकालिक सामाजिक हित आर्थिक चिंताओं से ऊपर हैं। 1 फरवरी 2026 से लागू होने वाली यह नई कर व्यवस्था आने वाले समय में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की खपत, बाजार और कीमतों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाने वाली है।

संपादकीय

कई सवालों के जवाब देगा नया साल, 2026 में राजनीतिक मोर्चे पर काफी कुछ दांव पर लगा है

देश के राजनीतिक परिदृश्य को निर्धारित करने के दृष्टिकोण से अगला वर्ष बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगले वर्ष बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें सभी दलों का कुछ न कुछ दांव पर लगा हुआ है। सबसे धनाढ्य नगर निकाय बृहनमुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के चुनाव भी होने हैं। कुछ राज्यसभा की रिक्त हो रही सीटों पर चुनाव की स्थिति में भी दलों के बीच खींचतान होती हुई दिख सकती है। अगला साल कई राजनीतिक पहेलियां भी सुलझाएगा। जैसे कि क्या देश भर में बड़े पैमाने पर विस्तार कर चुकी भाजपा अपने लिए राजनीतिक रूप से अनुर्वर साबित हो रहे प्रदेशों में भी अनुकूल स्थितियां बनाकर पैठ बढ़ा पाएगी या नहीं? भारत जोड़ो यात्रा के बाद पटरी पर आई कांग्रेस की जो गाड़ी फिर से बेपटरी हुई, क्या वह वापस पटरी पर आ पाएगी या नहीं? क्या अस्तित्व के संकट से जूझ रहे वामदल अपनी सत्ता के आखिरी दुर्ग को बचा पाएंगे या नहीं? क्षेत्रीय दल किस नियति को प्राप्त होंगे?

भाजपा की चर्चा की जाए तो विधानसभा चुनाव इसकी पुष्टि करेंगे कि नए क्षेत्रों में पैठ बनाने के उसके प्रयासों को कितनी सफलता मिलेगी? जिन राज्यों में चुनाव होना है, वहां केवल असम में ही उसकी सरकार है और पुडुचेरी में उसके समर्थन वाली सरकार सत्तारूढ़ है। दस साल से असम की सत्ता पर काबिज भाजपा के लिए फिर से सत्ता में वापसी की ठीकठाक संभावनाएं तो दिख रही हैं, लेकिन यह तय है कि उसे इस बार गौरव गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल रही है। अगर कांग्रेस ने राजनीतिक कौशल दिखाया तो भाजपा के समीकरण गड़बड़ा भी सकते हैं। बंगाल में तमाम प्रयासों के बावजूद पार्टी दूसरे क्रम पर ही अटकी हुई है। ममता बनर्जी ने राज्य की सत्ता पर जिस मजबूती के साथ पकड़ बनाई हुई है, उससे भाजपा के लिए राह बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। हालांकि बिहार की जीत से उत्साहित भाजपा नई ऊर्जा के साथ बंगाल के रण में उतरने की तैयारी कर रही है। एक रणनीति के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी उसने जोर-शोर से उठाना शुरू कर दिया है।

दक्षिण में केरल और तमिलनाडु भाजपा के लिए दूर की कौड़ी बने हुए हैं। लोकसभा की 39 सीटों वाले तमिलनाडु में भरसक कोशिशों के बावजूद पिछले लोकसभा चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में वह यहां गठबंधन सहयोगियों के ही भरोसे है। केरल की दो ध्रुवीय राजनीति में भाजपा फिलहाल तीसरा ध्रुव बनने पर ही ध्यान टिकाए हुए है। तिरुअनंतपुरम के निकाय चुनाव में जीत से उसे थोड़ी ही सही, लेकिन ताकत और हौसला जरूर मिला है। ऐसे में देखना यही होगा कि विधानसभा चुनावों में पार्टी कितनी मजबूती से अपनी चुनौती पेश करती है?

कांग्रेस के लिए अगला साल कम चुनौतीपूर्ण नहीं होने वाला। असम में वापसी की आस लगाए बैठी कांग्रेस बंगाल में तो लगभग हाशिए पर पहुंच गई है। तमिलनाडु में वह द्रमुक की पिछलग्गू बनकर रह गई है। पार्टी की वास्तविक उम्मीदें केरल से जुड़ी हुई हैं, जहां वह वाम दलों के मोर्चे से सत्ता झटकने की व्यूह रचना बनाने में जुटी है। उसके लिए अनुकूल संकेत हैं कि हाल के निकाय चुनाव में पार्टी को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। हालांकि अतीत के कई चुनावों में जीती हुई बाजी हारने के लिए जानी-जाने वाली कांग्रेस के लिए केरल में भी समस्याएं कम नहीं हैं। पार्टी में नेतृत्व को लेकर खींचतान की स्थिति है। स्थानीय इकाई में गुटबाजी के अलावा प्रदेश नेतृत्व को ताकतवर महासचिव केसी वेणुगोपाल को लेकर भी आशंकाएं कम नहीं हैं कि सत्ता मिलने पर वह मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना दावा पेश कर सकते हैं। एक समय राज्य में पार्टी नेतृत्व को लेकर स्पष्टता का रुख रहा है, लेकिन एके एंटनी के केंद्र की राजनीति में जाने के बाद से प्रदेश में नेतृत्व को लेकर स्वीकार्यता की स्थिति बनाने में संघर्ष ही करती रही है। इसे यदि समय से नहीं सुलझाया गया तो केरल की सत्ता का सिंहासन उससे दूर ही रह जाएगा।

वामदलों के लिए भी अगला साल अस्तित्व के सवाल से जुड़ा है। लंबे समय से बंगाल और त्रिपुरा की सत्ता पर काबिज रहे वामदल अब इन दोनों राज्यों में राजनीतिक वनवास भोग रहे हैं। अगर केरल की सत्ता से भी उनकी विदाई होती है तो उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। एक ऐसे समय में जब यह विचारधारा भारत में अपने आगमन के सौ वर्षों का सफर पूरा कर चुकी है तो सत्ताशून्यता की ऐसी संभावित स्थिति उसकी वैचारिक प्रासंगिकता पर प्रश्न ही उठाएगी। कुछ अन्य क्षेत्रीय क्षत्रपों के लिए भी अगला साल बहुत कुछ निर्धारित करेगा। बंगाल में तृणमूल जिस जज्बे के साथ जुटी हुई है, उससे लगता नहीं कि वह प्रतिद्वंद्वी भाजपा को आसानी से राजनीतिक बढ़त बनाने की गुंजाइश देगी। हालांकि भाजपा जिस रणनीति और संसाधनों के साथ चुनाव लड़ती है उसे देखते हुए ममता बनर्जी के लिए भी राह आसान नहीं होगी। तमिलनाडु में द्रमुक का गढ़ कुछ अभेद्य लगता है, क्योंकि जयललिता के निधन के बाद राज्य में जो राजनीतिक निर्वात की स्थिति उत्पन्न हुई, उसकी अभी तक भरपाई नहीं हो सकी।

नया कालखंड, नए साल से नई उम्मीदें

> 2025 की विदाई के साथ ही देश उस नए कालखंड में प्रवेश कर रहा है, जब विकसित भारत का लक्ष्य और निकट आ गया है। यह लक्ष्य वास्तव में प्राप्त हो सके, इसके लिए मानसिकता में बदलाव लाना भी आवश्यक है। ऐसा करके ही हम अपनी कार्यसंस्कृति बदल सकेंगे और आने वाले कल की चुनौतियों से पार पा पाएंगे। हम सब मिलकर ऐसा कर सकें, इस आशा के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं।

नव वर्ष का आगमन सदैव नई आशाओं, नए संकल्पों और बेहतर भविष्य की अपेक्षाओं के साथ होता है। जैसे ही पुराना वर्ष विदा लेता है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से बीते समय का लेखा-जोखा करता है और आने वाले कल को अधिक सुंदर, अधिक सुरक्षित तथा अधिक समृद्ध बनाने के स्वप्न देखने लगता है। भारत जैसे देश में, जहां परंपरा, संस्कृति और दर्शन जीवन के हर पक्ष से जुड़े हुए हैं, नव वर्ष केवल कैलेंडर बदलने का अवसर नहीं होता, बल्कि आत्ममंथन और आत्मसुधार का भी एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। हम उस महान सांस्कृतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं, जिसने 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' और 'वसुधैव कुटुंबकम्' जैसे विचार संसार को दिए। यही कारण है कि नव वर्ष के अवसर पर हम केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए शुभ, मंगल और कल्याण की कामना करते हैं।

लेकिन इन शुभेच्छाओं और मंगल कामनाओं के बीच एक यथार्थ भी हमारे सामने खड़ा होता है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसे व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां आती हैं, वैसे ही समाज और राष्ट्र के जीवन में भी समस्याएं और कठिनाइयां आती रहती हैं। नया वर्ष कोई जादुई छड़ी नहीं है, जो बीते वर्ष की सभी समस्याओं को स्वतः समाप्त कर दे। चुनौतियां इस वर्ष भी आएंगी, प्रश्न केवल इतना है कि हम उनका सामना किस दृष्टि और किस तैयारी के साथ करते हैं। यदि हम केवल आशा के सहारे बैठ जाएं और अपने व्यवहार, अपनी सोच तथा अपनी कार्यशैली में बदलाव न लाएं, तो नए वर्ष का आगमन भी पुराने संकटों को नए रूप में हमारे सामने खड़ा कर देगा।

इससे अच्छा और सार्थक कुछ नहीं हो सकता कि इस नए वर्ष में हम चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को मानसिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से तैयार करें। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना

रहा है, लेकिन प्रगति का यह मार्ग सरल नहीं है। इस मार्ग में आर्थिक असमानता, सामाजिक विषमता, प्रशासनिक ढिलाई, संसाधनों का असंतुलित उपयोग, पर्यावरणीय संकट और नैतिक मूल्यों में गिरावट जैसी अनेक बाधाएं हैं। यदि हमें इन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना है, तो केवल योजनाओं और घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता होगी, जिसमें सुख और समृद्धि के साथ-साथ सामाजिक समरसता भी बढ़े।

यह परिवर्तन सबसे पहले हमारी कार्यसंस्कृति में आना चाहिए। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति उसकी कार्यसंस्कृति से जुड़ी होती है। यदि कार्य करने का तरीका सुस्त, लापरवाह और केवल औपचारिकता निभाने वाला होगा, तो संसाधन होने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते। भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, संसाधनों की भी कमी नहीं है, लेकिन कई बार इच्छाशक्ति और अनुशासन की कमी हमारे प्रयासों को कमजोर कर देती है। नए वर्ष में यह आवश्यक है कि हम कार्य को बोझ नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का साधन मानें। ईमानदारी, समयबद्धता और जिम्मेदारी को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा।

यद्यपि किसी भी देश की कार्यसंस्कृति बदलने का दायित्व मुख्य रूप से शासन और प्रशासन में बैठे लोगों का होता है, क्योंकि वही नीतियां बनाते हैं और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन यह मान लेना कि सारी जिम्मेदारी केवल उन्हीं की है, सही नहीं होगा। शासन और प्रशासन की सफलता या विफलता में जनता की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विश्व के अनेक देशों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि उनका उत्थान तब हुआ, जब वहां के शासकों के साथ-साथ आम नागरिकों ने भी राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पण भाव से योगदान दिया। जब नागरिक अपने कर्तव्यों को समझते हैं और उनका ईमानदारी से पालन करते हैं, तब शासन की योजनाएं धरातल पर उतरती हैं।

आज भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इतनी विशाल आबादी और विविध भाषा, धर्म, पंथ तथा संस्कृति वाले समाज को एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ाना आसान कार्य नहीं है। ऐसे में केवल सरकार से यह अपेक्षा करना कि वह सभी समस्याओं का समाधान कर देगी, व्यावहारिक नहीं है। शासन-प्रशासन और आम जनता के बीच सहयोग और विश्वास का रिश्ता मजबूत किए बिना प्रगति की गति बनाए रखना कठिन हो जाएगा। यह समझना आवश्यक है कि जैसे शासक का एक धर्म होता है, वैसे ही नागरिक का भी एक धर्म होता है, जिसे हम नागरिक धर्म कहते हैं।

हम अक्सर विभिन्न समस्याओं को लेकर शासन-प्रशासन को कठघरे में खड़ा करते हैं और यह कई बार उचित भी होता है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही अधिक होती है। लेकिन एक प्रश्न प्रायः अनुत्तरित रह जाता है कि क्या हम स्वयं अपने नागरिक धर्म का निर्वाह ईमानदारी से करते हैं। क्या हम नियमों का पालन केवल डर के कारण करते हैं या जिम्मेदारी के भाव से? क्या हम सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति की तरह सुरक्षित रखते हैं? क्या हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में योगदान देते हैं? क्या हम कर चुकाने, मतदान करने और कानून का सम्मान करने जैसे बुनियादी कर्तव्यों को गंभीरता से लेते हैं?

हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग होना ही चाहिए, क्योंकि अधिकारों के बिना लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता, लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्यों का संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। यदि हम केवल अपने अधिकारों की बात करें और कर्तव्यों से मुंह मोड़ लें, तो समाज में असंतुलन पैदा होगा। यह सत्य है कि कई समस्याएं शासन-प्रशासन की ढिलाई के कारण लंबित रहती हैं, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि अनेक समस्याएं इसलिए जटिल बनी रहती हैं, क्योंकि जनता का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता। जब नियमों का पालन नहीं किया जाता, जब व्यवस्था को चकमा देने को चतुराई समझा जाता है, तब किसी भी सुधार की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है।

यदि इस नए वर्ष में हम जन सहयोग की इस कमी को दूर करने का संकल्प लें, तो आत्मनिर्भर भारत की राह कहीं अधिक आसान हो सकती है। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक स्वावलंबन नहीं है, बल्कि मानसिक और सामाजिक आत्मनिर्भरता भी है। जब नागरिक यह मानने लगते हैं कि देश की प्रगति में उनकी भी सीधी भूमिका है, तब परिवर्तन की गति तेज हो जाती है। आत्मनिर्भरता विकसित राष्ट्र बनने की कुंजी है, क्योंकि जो देश अपने संसाधनों का सही उपयोग करना सीख लेता है और अपने लोगों की क्षमताओं पर भरोसा करता है, वही स्थायी विकास की दिशा में आगे बढ़ता है।

2025 की विदाई के साथ ही देश एक ऐसे नए कालखंड में प्रवेश कर रहा है, जहां विकसित भारत का लक्ष्य पहले से कहीं अधिक निकट दिखाई दे रहा है। यह लक्ष्य केवल आर्थिक आंकड़ों या अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध नागरिकों के जीवन स्तर, सामाजिक न्याय, समान अवसर और मानवीय मूल्यों से भी है। यदि हमें वास्तव में विकसित भारत का सपना साकार करना है, तो केवल बुनियादी ढांचे और तकनीक पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि मानसिकता में भी बदलाव लाना होगा।

मानसिकता में बदलाव का अर्थ है संकीर्ण सोच से बाहर निकलना, तात्कालिक लाभ की जगह दीर्घकालिक हितों को महत्व देना और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक कल्याण के बारे में सोचना। जब हम अपने छोटे-छोटे स्वार्थों को राष्ट्रहित के सामने रख देते हैं, तब विकास की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इसके विपरीत, जब हम यह समझ लेते हैं कि राष्ट्र मजबूत होगा तो नागरिक भी मजबूत होंगे, तब सहयोग और समर्पण की भावना स्वतः विकसित होती है।

नया वर्ष हमें यह अवसर देता है कि हम बीते अनुभवों से सीख लें और आने वाले समय के लिए बेहतर तैयारी करें। यह केवल सरकारों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए आत्ममंथन का समय है। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि हम अपने परिवार, समाज और देश के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। यदि हर व्यक्ति अपने स्तर पर ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता को अपनाने का संकल्प ले ले, तो बड़े-बड़े बदलाव संभव हैं।

प्रेरणा

क्रोध नहीं, विवेक बने मार्गदर्शक

मनुष्य के जीवन में टकराव और असहमति उतने ही स्वाभाविक हैं, जितनी सांसें लेना। जहां विचारों की विविधता होती है, वहां मतभेद भी जन्म लेते हैं। समस्या मतभेदों में नहीं, बल्कि उन्हें संभालने के हमारे तरीके में होती है। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि क्रोध के बिना अपनी बात मनवाना संभव नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि क्रोध समस्या को सुलझाने के बजाय और उलझा देता है। शांति और विवेक से लिया गया निर्णय ही जीवन को सही दिशा देता है। इसी सत्य को अब्राहम लिंकन के जीवन की एक छोटी-सी घटना अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उजागर करती है।

एक बार एक युवक अत्यधिक क्रोधित अवस्था में अब्राहम लिंकन के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था और उसकी आवाज में आक्रोश था। उसने शिकायत की कि उसके सहकर्मी ने उसका अपमान किया है और वह उसी तरह से जवाब देना चाहता है। युवक को लग रहा था कि यदि उसने प्रतिशोध नहीं लिया, तो उसका आत्मसम्मान समाप्त हो जाएगा। वह यह मान बैठा था कि चुप रहना कमजोरी है और क्रोध दिखाना ही ताकत का प्रमाण है।

लिंकन ने युवक की पूरी बात बहुत शांतिपूर्वक सुनी। उन्होंने उसे न तो तुरंत कोई उपदेश दिया और न ही उसके क्रोध को गलत ठहराया। इसके बजाय वे उसे अपने साथ खेतों की ओर ले गए। वहां खेतों के बीच एक संकरा सा रास्ता था, जिस पर कीचड़ जमा हुआ था। दोनों कुछ देर वहीं खड़े रहे। तभी सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी। रास्ता इतना तंग था कि एक समय में केवल एक ही गाड़ी निकल सकती थी।

लिंकन ने युवक से पूछा कि यदि दोनों गाड़ीवान अपनी-अपनी जिद पर अड़ जाएं और कहें कि पहले मैं ही निकलूंगा, तो क्या होगा। युवक ने बिना किसी हिचक के उत्तर दिया कि दोनों गाड़ियां वहीं फंस जाएंगी और आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। इसी साधारण से उत्तर में जीवन का गहरा सत्य छिपा था। लिंकन ने मुस्कुराते हुए कहा कि जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही रास्ता है। यदि हम हर मोड़ पर अपनी जिद को सर्वोपरि रखेंगे, तो न केवल स्वयं फंस जाएंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता रोक देंगे।

उन्होंने आगे समझाया कि कभी-कभी पीछे हटना हार नहीं, बल्कि समझदारी होती है। हर विवाद में जीतने की कोशिश करना आवश्यक नहीं होता। कई बार शांत रहकर स्थिति को संभाल लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। क्रोध में लिया गया निर्णय क्षणिक संतोष तो देता है, लेकिन उसका परिणाम अक्सर पछतावे के रूप में सामने आता है। इसके विपरीत, विवेक और शांति से लिया गया निर्णय दूरगामी लाभ देता है।

लिंकन ने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में असंख्य आलोचनाओं और अपमानों का सामना किया, लेकिन यदि वे हर बार क्रोध में प्रतिक्रिया देते, तो शायद वे अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाते। उन्होंने सीखा कि क्रोध मन को बोझिल बना देता है और बोझिल मन सही निर्णय नहीं ले सकता। शांत मन ही स्पष्ट सोच और सही दिशा प्रदान करता है।

युवक धीरे-धीरे लिंकन की बातों को समझने लगा। उसके भीतर उठ रहा आक्रोश शांत होने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि यदि वह भी अपने सहकर्मी की तरह क्रोध का रास्ता अपनाएगा, तो विवाद सुलझने के बजाय और बढ़ जाएगा। दोनों के बीच का संबंध और बिगड़ जाएगा और कार्यस्थल का वातावरण भी खराब होगा। उसने यह भी समझा कि संयम अपनाने से उसका सम्मान कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा।

आज के समय में यह सीख और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार, प्रतिस्पर्धा और तनाव ने लोगों को जल्दी गुस्सा करने वाला बना दिया है। छोटी-छोटी बातों पर विवाद, कटु शब्द और त्वरित प्रतिक्रिया आम हो गई है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया है, जहां लोग बिना सोचे-समझे अपनी भड़ास निकाल देते हैं। यदि हम थोड़ी देर रुककर सोचें और शांति से प्रतिक्रिया दें, तो अनेक विवाद स्वतः ही समाप्त हो सकते हैं।

यह समझना आवश्यक है कि शांति का अर्थ अन्याय को सहन करना नहीं है। शांति का अर्थ है सही समय और सही तरीके से अपनी बात रखना। संयम व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसे भीतर से मजबूत करता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। यही आंतरिक शक्ति उसे कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित बनाए रखती है।

लिंकन से मिलने के बाद युवक का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। वह अब अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि समझदारी से देना चाहता था। उसके मन का बोझ हल्का हो गया था और उसे मानसिक शांति का अनुभव हो रहा था। उसने यह समझ लिया था कि प्रतिशोध क्षणिक संतोष देता है, जबकि संयम स्थायी सम्मान और आत्मसंतोष प्रदान करता है। अंततः जीवन हमें बार-बार ऐसे संकरे रास्तों पर लाकर खड़ा करता है, जहां हमें चुनना होता है कि हम जिद का रास्ता अपनाएं या विवेक का। जो व्यक्ति विवेक और शांति को अपना मार्गदर्शक बनाता है, वही न केवल स्वयं आगे बढ़ता है, बल्कि दूसरों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करता है। यही सच्ची सफलता है और यही जीवन का वास्तविक अर्थ भी।

लापरवाही बढ़ा रही सड़क हादसों को, इसका समय से सही समाधान अनिवार्य है

देश में हर दिन कोई न कोई बड़ी सड़क दुर्घटना होती है। कभी-कभी तो एक ही दिन कई जानलेवा हादसे होते हैं, जिनमें कई लोग मारे जाते हैं। इधर घने कोहरे के कारण मार्ग दुर्घटनाओं का जोखिम और बढ़ गया है। पिछले दिनों घने कोहरे के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में कई मार्ग दुर्घटनाएं हुईं। इनमे सबसे भंयकर रही आगरा से नोएडा जाने वाले एक्सप्रेसवे पर। यहां एक कार और बस की टक्कर होने के बाद एक के बाद एक कुल 11 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिनमें छह स्लीपर कोच और दो रोडवेज बसें भी थीं।

टक्कर के बाद कई वाहनों में आग लग गई, जिसमें दर्जन भर लोग जिंदा जलकर मर गए, जिनकी पहचान मुश्किल हो गई। एंबुलेंस, पुलिस, फायर सर्विस अथवा परिवहन से संबंधित कोई इकाई उनकी मदद नहीं कर सकी। डीएनए टेस्ट द्वारा उनके संबंधियों से मिलान कर शवों की पहचान की गई। उन परिवारों की पीड़ा का बयान शब्दों में संभव नहीं। ऐसी हर दुर्घटना के पीछे लापरवाही होती है।

जब रात्रि के घने कोहरे में पैदल यात्रियों को भी चलना दूभर हो जाता है, तब पूरी रफ्तार से बिना आवश्यक सावधानी के स्लीपर या रोडवेज बसों का चलना गंभीर अपराध कहा जाएगा। यदि चालक अत्यधिक ड्यूटी के कारण नींद की झपकी ले रहे थे या वाहनों में आवश्यक फाग लाइटें नहीं थीं, अथवा कोई अन्य तकनीकी कमी थी तो यह बस मालिकों की भी गंभीर लापरवाही मानी जाएगी। पूरा देश जानता है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में प्रतिवर्ष पूरे उत्तर भारत में कोहरा पड़ता है, जो अचानक किसी दिन घने, किसी दिन बहुत घने और कभी बहुत हल्का होता है।

आगरा-नोएडा एक्सप्रेसवे पर जिस दिन दुर्घटना हुई, उसके दो दिन पूर्व घने कोहरे के कारण लखनऊ इकाना स्टेडियम में होने वाला क्रिकेट मैच खिलाड़ियों के मैदान में उतर जाने के बाद भी स्थगित करना पड़ा था। मौसम विभाग की चेतावनी भी कोहरे को लेकर थी, परंतु इन गाड़ियों की रफ्तार नियंत्रण और चेकिंग इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कम से कम कुछ चेकपोस्टों पर लाउडस्पीकरों से घोषणा कर वाहन चालकों को आगाह किया जा सकता था, लेकिन किसी को चिंता नहीं थी। प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ?

इसका मूल कारण किसी उच्चतम अधिकारी की स्पष्ट जिम्मेदारी का न होना है। इसका कारण यह है कि किसी की जवाबदेही नहीं होती और न ही कोई चिंता करता है। परिवहन विभाग ट्रैफिक पुलिस पर और ट्रैफिक पुलिस परिवहन विभाग पर दोष डालकर शांत हो जाते हैं और कुछ दिन बाद घटना भुला दी जाती है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी अब चौराहों तक सीमित है, ताकि यातायात अबाध रूप से चलता रहे।

आगरा-एक्सप्रेसवे पर भयंकर दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कठोर रुख अपनाते ही दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण सक्रिय हो गया। आगरा, लखनऊ, बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 50 पायलट गाड़ियां तैनात कर दी गईं और 75 संवेदनशील स्थान भी चुन लिए गए, जहां से गाड़ियां काफिले में नियंत्रित गति से चलाना प्रारंभ की गईं। चिह्नित स्थानों पर ब्लिंकर्स लगाए गए। जगह-जगह लाउडस्पीकर लगाकर सतर्क करने की व्यवस्था की गई। इन चारों एक्सप्रेसवे पर हर 50 किमी की दूरी पर विशेष वाहनों की तैनाती की गई, जिसमें गश्ती वाहन, एंबुलेंस और रेस्क्यू वाहन लगाए गए। गाड़ियों को प्रवेश बिंदुओं पर रोककर रिफ्लेक्टर और फाग लाइटें लगाई गईं। अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था की गई। वाहनों की गति सीमा निर्धारित कर उसे लागू किया गया और न मानने वालों के चालान काटे गए। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यह सब पहले नहीं किया जा सका। पुलिस और प्रशासन दुर्घटना होने के बाद चेतता है। इसका एक कारण यह है कि देश भर में आम तौर पर यातायात पुलिस को शहर के चौराहों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में पुलिस से अधिक प्रभावशाली योगदान किसी और विभाग का हो ही नहीं सकता।

सभी प्रदेशों में थानों-चौकियों के जरिये हर कहीं यातायात पुलिस की पहुंच है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पुलिस 24 घंटे ड्यूटी को उपलब्ध रहती है और किसी भी घटना स्थल पर सबसे पहले वही पहुंचती है। पूरे देश में प्रतिवर्ष लगभग 1,60,000 दुर्घटनाएं होती हैं। मार्ग दुर्घटनाओं में मरने और घायल होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर उनके प्रति अफसोस प्रकट कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। कभी-कभी लगता है कि वाहन चालकों को कानून का कोई भय ही नहीं है। इस व्यवस्था में सुधार तब तक संभव नहीं है, जब तक कि एक विभाग विशेष की जवाबदेही तय नहीं कर दी जाती। जिम्मेदारी जवाबदेही से आती है। यही विभाग अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर पूरे वर्ष बदलते मौसम, त्योहारों, विशेष यात्राओं इत्यादि को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार हो।

अपने देश में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो देश के विकास के साथ-साथ भविष्य में दोगुनी गति से बढ़ेगी। लिहाजा यातायात पर विशेष ध्यान देते हुए सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना चाहिए और शानदार हाईवे भी बनाए जाने चाहिए। सड़क सुरक्षा भविष्य में बहुत बड़ी प्रशासनिक समस्या होने वाली है। इसका समय से सही समाधान आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है।

अभियान

पद्मनाभस्वामी मंदिर का सातवां द्वार: आस्था, रहस्य और भय के बीच खड़ा एक अनसुलझा सच

केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभस्वामी मंदिर केवल एक प्राचीन धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में गिना जाता है। सदियों से यह मंदिर श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा है, लेकिन बीते कुछ दशकों में इसकी पहचान एक ऐसे रहस्य से जुड़ गई है, जिसने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, न्यायपालिका और आम जनमानस—सभी को चकित और चिंतित कर दिया है। यह रहस्य है पद्मनाभस्वामी मंदिर का सातवां द्वार, जिसे आज तक खोला नहीं गया है और जिसके खुलने से दुनिया डरती है।

यह भय केवल अंधविश्वास का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी पौराणिक मान्यताएं, ऐतिहासिक घटनाएं, अप्रत्याशित संयोग और धार्मिक चेतावनियां जुड़ी हुई हैं। वर्ष 2011 में जब मंदिर के छह तहखानों के दरवाजे खोले गए, तब जो सामने आया, उसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। सोने-चांदी के भंडार, हीरे-जवाहरात, स्वर्ण सिंहासन, प्राचीन मुद्राएं और अनमोल आभूषण—इन सबका मूल्य आज भी ठीक-ठीक आंका नहीं जा सका है। लेकिन इसी खोज के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यह उठा कि आखिर सातवें द्वार के पीछे क्या है, जिसे आज भी नहीं खोला गया? पद्मनाभस्वामी मंदिर का यह सातवां द्वार, जिसे 'बी वॉल्ट' या 'कल्लारा बी' कहा जाता है, बाकी सभी तहखानों से अलग है। जहां अन्य तहखानों के दरवाजे लोहे के बने हैं, वहीं यह द्वार लकड़ी से निर्मित है और उस पर एक विशाल नाग की आकृति उकेरी गई है। यही नाग आकृति इस द्वार को रहस्य और भय का केंद्र बनाती है। मान्यता है कि यह द्वार साधारण ताले से बंद नहीं है, बल्कि इसे मंत्रों द्वारा सुरक्षित किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस तहखाने के द्वार को केवल वही पुजारी खोल सकता है, जिसे 'गरुड़ मंत्र' के पूर्ण और शुद्ध जाप का सिद्ध ज्ञान हो। यह मंत्र इतना शक्तिशाली माना जाता है कि इसके उच्चारण से ही द्वार स्वतः खुल सकता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि यदि किसी अयोग्य या अपवित्र व्यक्ति ने इस मंत्र का प्रयोग करने की कोशिश की, तो भयानक अनिष्ट घट सकता है। कथाओं के अनुसार, इस द्वार की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप नाग करते हैं।

कई संतों और विद्वानों का मानना है कि इस तहखाने में केवल खजाना ही नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा भी बंद है। कुछ लोग इसे दिव्य ऊर्जा मानते हैं, तो कुछ इसे विनाशकारी शक्ति से जोड़कर देखते हैं। यही कारण है कि जब वर्ष 2011 में मंदिर के अन्य तहखानों को खोला गया, तब सातवें द्वार को खोलने पर भारी विवाद हुआ। कई साधु-संतों, ज्योतिषियों और धार्मिक नेताओं ने चेतावनी दी कि इस द्वार को खोलना देवद्रोह होगा।

इस विवाद ने तब और गंभीर रूप ले लिया, जब कुछ अप्रत्याशित घटनाएं सामने आईं। तहखानों की जांच से जुड़े कुछ अधिकारियों और विशेषज्ञों की असामयिक मृत्यु, समुद्र में अचानक आई ऊंची लहरें, और केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में असामान्य प्राकृतिक घटनाओं को लोगों ने इस रहस्य से जोड़ दिया। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से इन घटनाओं का कोई ठोस संबंध सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन जनमानस में यह धारणा और गहरी होती चली गई कि सातवां द्वार किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ा है।

मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के प्रबंधन और खजाने की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, लेकिन सातवें द्वार को खोलने की अनुमति नहीं दी। अदालत ने यह माना कि इस विषय में धार्मिक भावनाएं, परंपराएं और संभावित खतरे इतने गहरे हैं कि जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। यह निर्णय अपने आप में असाधारण था, क्योंकि आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था में धार्मिक मान्यताओं को इतनी बड़ी प्राथमिकता मिलना विरल है।

इतिहास की ओर देखें तो पद्मनाभस्वामी मंदिर का निर्माण त्रावणकोर के राजाओं द्वारा कराया गया था। त्रावणकोर के शासक स्वयं को भगवान विष्णु का दास मानते थे। वर्ष 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने 'त्रिपाददानम्' की घोषणा करते हुए अपना राज्य, संपत्ति और वैभव भगवान पद्मनाभस्वामी को समर्पित कर दिया था। इसके बाद से त्रावणकोर के राजा स्वयं को 'पद्मनाभ दास' कहने लगे। यही कारण है कि मंदिर की संपत्ति को व्यक्तिगत नहीं, बल्कि भगवान की संपत्ति माना गया। मंदिर की स्थापत्य कला भी इसे अद्वितीय बनाती है। यह केरल और द्रविड़ स्थापत्य शैली का अद्भुत संगम है। ऊंचा गोपुरम, जटिल नक्काशी, पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां और भीतर गर्भगृह में विराजमान भगवान विष्णु की 18 फीट लंबी प्रतिमा—यह सब मंदिर को दिव्यता प्रदान करता है। भगवान विष्णु यहां शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं, जिन्हें देखने के लिए तीन द्वारों से दर्शन किए जाते हैं—पैर, नाभि और मुख।

सातवें द्वार से जुड़े भय को केवल धार्मिक अंधविश्वास कहकर खारिज करना भी सरल नहीं है। भारत की प्राचीन परंपरा में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि ऊर्जा केंद्र माने जाते रहे हैं। कई प्राचीन मंदिरों के गर्भगृह और तहखाने विशेष ज्यामितीय और खगोलीय गणनाओं के आधार पर बनाए गए थे। ऐसे में यह संभावना भी व्यक्त की जाती है कि सातवें द्वार के पीछे कोई ऐसी संरचना या तत्व हो, जिसे बिना पूरी तैयारी के छेड़ना खतरनाक हो सकता है।

वहीं दूसरी ओर, आधुनिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग मानते हैं कि इस द्वार को न खोलना केवल भय और अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। उनके अनुसार, खजाना राष्ट्र की धरोहर है और उसे सुरक्षित व पारदर्शी तरीके से संरक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन इस तर्क के जवाब में धार्मिक पक्ष यह कहता है कि यह खजाना किसी राजा या सरकार का नहीं, बल्कि भगवान का है और इसे हाथ लगाना आस्था का अपमान होगा।

आज स्थिति यह है कि पद्मनाभस्वामी मंदिर का सातवां द्वार बंद है, रहस्य बना हुआ है और यही रहस्य इसकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। यह द्वार मानो आस्था और तर्क, विज्ञान और विश्वास, आधुनिकता और परंपरा के बीच खड़ी एक सीमा रेखा है। इसे खोलना या न खोलना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत प्रश्न बन चुका है।

अंततः यही कहा जा सकता है कि पद्मनाभस्वामी मंदिर का सातवां द्वार केवल लकड़ी और नाग आकृति से बना एक दरवाजा नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की उस गहरी मानसिकता का प्रतीक है, जहां श्रद्धा और भय साथ-साथ चलते हैं। यह द्वार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर रहस्य को सुलझाना आवश्यक है, या कुछ रहस्यों का रहस्य बने रहना ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। शायद इसी कारण दुनिया आज भी पद्मनाभस्वामी मंदिर के सातवें द्वार से डरती है—क्योंकि इसके पीछे केवल खजाना नहीं, बल्कि हमारी आस्था की परीक्षा छिपी हुई है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो–2026

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 'भारत एक गाथा' थीम के साथ 14वें इंटरनेशनल फ्लावर शो का शुभारंभ कराया

ऊर्जा राज्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल तथा शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला की प्रेरक उपस्थिति

- लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के राष्ट्रीय एकता में योगदान को सम्मानित करने वाला विश्व का सबसे बड़ा फूलों से बना चित्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तैयार कराया गया
- मुख्यमंत्री के करकमलों से 'नारी सशक्तिकरण' थीम पर तैयार किए गए स्कल्पचर का भी अनावरण कराया गया
- यूनेस्को द्वारा घोषित 'विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर – दिवाली' पर विशेष कृति प्रस्तुत की गई
- फूल, कला और कल्पना के संगम से भारत के इतिहास, संस्कृति, उपलब्धियों और भावनाओं को एक ही मंच पर प्रस्तुत किया गया
- 22 जनवरी 2026 तक फ्लावर शो- 2025 की मुलाकात ले सकेंगे

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को साबरमती रिवरफ्रंट पर 'अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो–2026' का शुभारंभ किया। 'भारत एक गाथा' थीम पर इंटरनेशनल फ्लावर शो के 14वें संस्करण का आयोजन किया गया है। भारत की समृद्ध, विविधतापूर्ण और गौरवशाली संस्कृति को प्रस्तुत करने वाले इस भव्य उत्सव का आगामी 22 जनवरी तक आनंद लिया जा सकेगा।

इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल तथा शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला भी उपस्थित रहे। 'अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो–2026' के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री सहित सभी अतिथियों ने फ्लावर शो के विभिन्न जोनों का अवलोकन किया और विभिन्न आकर्षणों को देखा। साथ ही, सभी ने अनेक प्रकार के फूलों से बने स्कल्पचर की सराहना की। इस प्रदर्शनी में 'नारी सशक्तिकरण' थीम पर तैयार किए गए स्कल्पचर का भी मुख्यमंत्री के करकमलों से अनावरण किया गया। इसके अतिरिक्त, यहाँ लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के राष्ट्रीय एकता में दिए गए योगदान को सम्मानित करने वाला विश्व का सबसे बड़ा फूलों से बना स्कल्पचर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तैयार किया गया है। साथ ही, यूनेस्को द्वारा घोषित 'विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर – दिवाली' पर विशेष कृति भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेगी। उल्लेखनीय है कि प्रदर्शनी के विभिन्न जोन भारत के अलग-अलग आयामों को उजागर करेंगे, जिनमें प्राचीन ज्ञान, उत्सवों का उल्लास, कलात्मक तेजस्विता और आधुनिक विकास की गाथा शामिल है। आगंतुक एक जोन से दूसरे जोन में आगे बढ़ते हुए प्राचीन से आधुनिक भारत की सम्पूर्ण समय-यात्रा का अनुभव करे सकेंगे और 'विविधता में एकता' की भावना को नजदीक से महसूस कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, विशेष ऑडियो गाइड भी बनाए गए हैं। फ्लावर शो में विभिन्न स्थानों पर क्यूआर कोड स्कैन कर फूलों, स्कल्पचर व जोनों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। साथ ही, सोवेनियर शॉप, नर्सरी, चाइल्ड केयर यूनिट और फूड स्टॉल भी आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। जन भागीदारी से आयोजित इस फ्लावर शो में कई स्वतंत्र कॉर्पोरेट और सरकारी इकाइयां भागीदार बनी हैं। इस अवसर पर अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, अहमदाबाद के विधायक सर्वश्री अमित ठाकर, जीतूभाई पटेल, हर्षदभाई पटेल, उप महापौर श्री जतिनभाई पटेल, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री देवांगभाई दाणी, महानगर पालिका आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि, मनपा के पदाधिकारी, अधिकारी तथा कॉर्पोरेट इकाइयों के प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

इंटरनेशनल फ्लावर शो–2026 के प्रमुख आकर्षण

- भारत की पौराणिक धरोहर को प्रस्तुत करने वाला 'शाश्वत भारत' जोन और 30 मीटर व्यास का भव्य फूल मंडल फ्लावर शो का प्रमुख आकर्षक
- देश की हाई-स्पीड रेल, नवीकरणीय ऊर्जा, स्पोर्ट्स क्षेत्र की उपलब्धियों, अंतरिक्ष टेक्नॉलोजी और शिक्षा क्षेत्र की प्राप्त सफलताओं को फूलों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया

विश्व स्तरीय अहमदाबाद फ्लावर शो–2026 भारतीय संस्कृति और प्रकृति की सुंदरता का संगम प्रस्तुत करता है। इस वार्षिक रंगोत्सव में पूरे भारत से प्रकृति और संस्कृति प्रेमी सहभागी होते हैं। इतना ही नहीं, यह शो फूलों की भव्यता के साथ मानवीय कलाकारी की अनगिनत स्मृतियां भी साथ लेकर जाने का अनुभव कराता है।

यह फूल महोत्सव केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि पर्यावरण जागरूकता तथा सस्टेनेबिलिटी के साथ ही अहमदाबाद शहर की जैवविविधता और इकोफ्रेंड्ली सिस्टम को और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर इस फ्लावर शो में संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करता है।

फ्लावर शो की यात्रा भव्य प्रवेश द्वार से आरंभ होगी, जहां दो विशाल फूलों से बने सिंह आगंतुकों का स्वागत करेंगे। ये सिंह भारत की वीरता, गौरव और अडिग आत्मा के प्रतीक होंगे। प्रवेश जोन में कमल के फव्वारों द्वारा राष्ट्रीय गौरव को फूलों से सजाकर प्रस्तुत किया जाएगा, जो पूरी प्रदर्शनी की थीम के अनुरूप गौरवमय वातावरण का निर्माण करेगा।

प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न उत्सवों को समर्पित विशेष जोन भी तैयार किए गए हैं। यहां फूलों की कला के माध्यम से दिवाली के प्रकाश, आशा के संदेश, होली के रंग और उल्लास, ओणम की परंपरागत सौम्यता और बिहू के लयबद्ध उत्सवों को जीवंत स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों के लिए विशेष रंगीन और आनंदमय जोन भी तैयार किया गया है, जहां कार्टून किरदारों द्वारा बच्चों के लिए मनोरंजन तथा कल्पना के विश्व का निर्माण किया जाएगा।

आगंतुकों की सुविधा हेतु चार विशेष प्रवेश द्वार

- गेट नंबर 1 – फ्लावर पार्क, एलिसब्रिज के पास, रिवरफ्रंट पश्चिम
- मल्टीलेवल कार पार्किंग फुटओवर ब्रिज के ऊपर से
- गेट नंबर 4 – इवेंट सेंटर, रिवरफ्रंट पश्चिम
- पूर्व प्रवेश – अटल ब्रिज का पूर्वी छोर, रिवरफ्रंट पूर्व

भारत की पौराणिक धरोहर को प्रस्तुत करने वाला 'शाश्वत भारत' जोन भी फ्लावर शो का मुख्य आकर्षक बनेगा। आध्यात्मिक रूप से समृद्ध इस जोन में समुद्र मंथन, गीता सार, गोवर्धन लीला, गंगा अवतरण और रामसेतु जैसे पौराणिक प्रसंगों को फूलों की मूर्तियों के माध्यम से कलात्मक रूप से पुनः सृजित किया गया है, जो आगंतुकों को भारत की प्राचीन सांस्कृतिक कथाओं से जोड़ते हैं।

इसके साथ ही भारतीय शास्त्रीय और लोकनृत्य परंपराओं को समर्पित जोन में कुचिपुड़ी, भांगड़ा, गरबा और कथकली जैसे नृत्य रूपों की सौम्यता प्रस्तुत की जाएगी। इस जोन के केंद्र में भगवान नटराज की प्रतिमा भारत की कलात्मक समृद्धि, परंपरा की निरंतरता और ताल की सर्वव्यापी भाषा का प्रतीक बनेगी।

आधुनिक भारत की प्रगति को दर्शाने वाला 'भारत की उपलब्धियां' जोन फूलों के माध्यम से देश की हाई-स्पीड रेल, नवीकरणीय ऊर्जा, स्पोर्ट्स क्षेत्र की उपलब्धियां, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा क्षेत्र में प्राप्त की गई उत्कृष्टता को प्रस्तुत करेगा। यह जोन भारत की विरासत और भविष्याभिमुख नवाचार के संतुलित विकास की एक शक्तिशाली गाथा प्रस्तुत करेगा।

प्रदर्शनी का एक प्रमुख केंद्रबिंदु राष्ट्रीय एकता का प्रतीकात्मक जोन होगा, जिसमें 30 मीटर व्यास का भव्य फूल मंडल तथा सरदार वल्लभभाई पटेल का विश्व का सबसे बड़ा फूलों से बना चित्र प्रस्तुत किया जाएगा। भारत के लौह पुरुष के रूप में पहचाने जाने वाले सरदार पटेल के राष्ट्रीय एकता में दिए गए योगदान को सम्मानित करने वाली यह प्रदर्शनी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए तैयार की गई है।

अहमदाबाद महानगर पालिका द्वारा फ्लावर शो–2026 अंतर्गत साबरमती रिवरफ्रंट पर इवेंट ग्राउंड में डिसप्ले के लिए लगाए गए मौसमी पौधों की देखभाल करने के लिए ट्रैक्टर या पाइप जैसी पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों के स्थान पर 10,524 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्प्रिंकलर इरीगेशन नेटवर्क सिस्टम स्थापित किया गया है।

टिकट दर एवं समय

आगंतुकों के लिए सोमवार से शुक्रवार प्रवेश शुल्क 80 रुपए तथा शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में प्रवेश शुल्क 100 रुपए रहेगा। इसके अतिरिक्त, सभी प्रकार के दिव्यांगजनों, सैनिकों, 12 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों तथा अहमदाबाद महानगर पालिका संचालित स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए सभी दिनों में निःशुल्क प्रवेश रहेगा।

अहमदाबाद महानगर पालिका के अलावा अन्य स्कूलों के बच्चों के लिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से 1 बजे तक प्रवेश शुल्क 10 रुपए रहेगा। इसके अतिरिक्त, आगंतुकों के लिए सुबह 8 से 9 बजे तथा रात 10 से 11 बजे तक प्राइम टाइम स्लॉट में प्रवेश शुल्क 500 रुपए रहेगा।

नेपाल सीमा पर कारोबारी की पुलिस फायरिंग में मौत सड़क पर हंगामा और पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जाम

(जीएनएस)। अररिया। भारत-नेपाल सीमा के समीप सुनसरी जिले में नववर्ष के पहले दिन एक कारोबारी विजय साह की नेपाल पुलिस की फायरिंग में मौत ने क्षेत्र में भारी तनाव पैदा कर दिया है। घटना के बाद कोसी गाउँपालिका और लौकही क्षेत्र में दिनभर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच टकराव चलता रहा, जिससे नेपाल का प्रमुख पूर्व–पश्चिम राजमार्ग पूरी तरह जाम हो गया और आवागमन ठप पड़ गया। स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और मृतक विजय साह का शव सड़क पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश में पुलिस चौकी में आग लगा दी और विरोध के स्वर बढ़ते चले गए। स्थानीय प्रशासन और नेपाल पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पथराव और पेट्रोल बम फेंककर जवाबी कार्रवाई की। झड़पों में दर्जनों सशस्त्र पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस बीच जिला पुलिस कार्यालय सुनसरी ने अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखी हुई है।

जानकारी के अनुसार, विजय साह रात में भारत से नेपाल सामान ले जा रहे थे, तभी सशस्त्र पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। वाहन न रुकने पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें उनका मौके पर ही निधन हो गया। पुलिस ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई बताया, जबकि स्थानीय लोग इसे योजना बद्ध हत्या बताते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। घटनास्थल से खोखे बरामद किए गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही फायरिंग से जुड़े तथ्य स्पष्ट होंगे।

घटना के बाद सीमा क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों की नाराजगी उबल रही है, जिससे कई जगह सड़कें जाम हैं और आवाजाही प्रभावित हुई है। स्थानीय प्रशासन अब स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन व्यापक विरोध और हिंसा के कारण परिस्थितियां काफी गंभीर बनी हुई हैं।

व्यापारियों का कहना है कि इस घटना से न केवल उनकी सुरक्षा खतरे में है, बल्कि सीमावर्ती व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। वहीं, सोशल मीडिया पर भी इस घटना ने लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है और स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है कि वे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा।

नेपाल-भारत सीमा पर यह घटना न केवल स्थानीय व्यापार और आवागमन को प्रभावित कर रही है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक तनाव को भी बढ़ा रही है। स्थानीय लोग लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और सीमावर्ती व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में तनाव, अव्यवस्था और डर का माहौल बना हुआ है, और सामान्य स्थिति लौटने में अभी कुछ समय लग सकता है।

माघ मेला 2026: त्रिवेणी संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के लिए तैयार व्यवस्थाएँ, पहला स्नान कल

(जीएनएस)। प्रयागराज। त्रिवेणी संगम तट पर माघ मेला 2026 का आगाज तीन जनवरी से होने जा रहा है। यह मेला 44 दिनों तक चलेगा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ समापन होगा। पहले स्नान का अवसर पौष पूर्णिमा के दिन होगा, जबकि महाशिवरात्रि को अंतिम स्नान का पर्व मनाया जाएगा। इस धार्मिक मेले में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु, साधु-संत, कल्पवासी और तीर्थ यात्री संगम के पावन जल में स्नान कर पुण्य, शांति और मोक्ष की कामना करेंगे। माघ मेला विशेष रूप से प्रमुख स्नान पर्वों के कारण प्रसिद्ध है। तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को वसंत पंचमी, एक फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर स्नान करने का विशेष महत्व है। इन तिथियों को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है और इनके दौरान संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है।

मेला प्रशासन ने आयोजन को सुचारु और सुरक्षित रूप से सम्पन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। संगम तट और आसपास के क्षेत्रों में कुल 42 समर्पित पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालु अपने वाहन सुरक्षित रूप से खड़ा कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक नीरज पांडेय ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है। पुलिस बल को तट और आसपास के मार्गों पर तैनात किया गया है, ताकि भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों को तुरंत संभाला जा सके। संगम पर दर्शन और स्नान के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, नौ पंटून पुल, आपात सेवाओं के व्यापक इंतजाम, और 450 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की है। इस व्यवस्था के तहत श्रद्धालु बिना किसी कठिनाई के अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे।

माघ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सनातन संस्कृति, आस्था और परंपरा का जीवंत उदाहरण भी है। आधुनिक प्रबंधन और बेहतर सुविधाओं के साथ यह मेला श्रद्धालुओं के लिए भक्ति, आध्यात्म और सांस्कृतिक अनुभव का महापर्व बन जाता है। प्रशासन ने अलग-अलग रूट और पार्किंग के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की हैं, ताकि कल्पवार्षियों और तीर्थ यात्रियों का आगमन और निकास सहज हो सके।

माघ मेला हर साल देशभर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और इस बार भी संगम तट पर आस्था और उत्साह की लहर देखने को मिलेगी। प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त तैयारियों से श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित मेला अनुभव प्रदान करने का प्रयास किया गया है। संगम के पावन जल में डुबकी लगाकर श्रद्धालु न केवल पुण्य कमाएंगे, बल्कि जीवन में शांति, मोक्ष और समृद्धि की कामना भी करेंगे।

सोना वायदा में 114 रुपये, चांदी वायदा में 73 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा में 1 रुपये की नरमी

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 64514.58 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 15797.56 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 48715.97 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 34870 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 1094.51 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 12033.75 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 135299 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 135890 रुपये और नीचे में 135080 रुपये पर पहुंचकर, 135804 रुपये के पिछले बंद के सामने 114 रुपये या 0.08 फीसदी औंधकर 135690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 14 रुपये या 0.01 फीसदी की बढ़त के साथ 111950 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 2 रुपये या 0.01 फीसदी की गिरावट के साथ 13942 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। सोना-मिनी फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 135687 रुपये के भाव पर खूलकर, 135850 रुपये के दिन के उच्च और 135001 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 71 रुपये या 0.05 फीसदी की गिरावट के साथ 135700 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 136411 रुपये के भाव पर खूलकर, 136886 रुपये के दिन के उच्च और 136140 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 136697 रुपये के पिछले बंद के सामने 43 रुपये या 0.03 फीसदी की बढ़त के साथ 136740 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 235998 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 238911 रुपये और नीचे में 233850 रुपये पर पहुंचकर, 235873 रुपये के पिछले बंद के सामने 73 रुपये या 0.03 फीसदी गिरकर 235800 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 206 रुपये या 0.09 फीसदी औंधकर 237792 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 129 रुपये या 0.05 फीसदी गिरकर 237881 रुपये प्रति किलो हुआ।

- कमोडिटी वायदाओं में 15797.56 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 48715.97 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 12033.75 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 34870 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 1789.87 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 1.5 रुपये या 0.12 फीसदी घटकर 1291 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 10 पैसे या 0.03 फीसदी के सुधार के साथ 308.15 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 10 पैसे या 0.03 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 297.4 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 5 पैसे या 0.03 फीसदी की नरमी के साथ 182.7 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1963.11 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5203 रुपये के भाव पर खूलकर, 5230 रुपये के दिन के उच्च और 5202 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1 रुपये या 0.02 फीसदी की गिरावट के साथ 5222 रुपये प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 1 रुपये या 0.02 फीसदी औंधकर 5222 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा 3 3 3 . 2 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 335.6 रुपये और नीचे में 317.1 रुपये पर पहुंचकर, 329.5 रुपये के पिछले बंद के सामने बिना बदलाव के 329.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 20 पैसे या 0.06 फीसदी की नरमी के साथ 329.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर बंद हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 1020 रुपये के भाव पर खूलकर, 2.9 रुपये या 0.29 फीसदी लुढ़ककर 1005.2 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 6325.94 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 5707.81 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1543.33 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 113.15 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 4.52 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 128.88 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 176.05 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1775.34 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 19019 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 88143 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 27538 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 415614 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 47090 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 17188 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 40887 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 104547 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 20739 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 39562 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 34801 पॉइंट पर खूलकर, 34899 के उच्च और 34765 के नीचले स्तर को छूकर, 19 पॉइंट बढ़कर 34870 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 1.9 रुपये की गिरावट के साथ 134.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 330 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 15 पैसे की नरमी के साथ 25.15 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 12.5 रुपये की गिरावट के साथ 1508 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 260000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 8.5 रुपये की बढ़त के साथ 7800 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 19 पैसे के सुधार के साथ 72 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 42 पैसे की नरमी के साथ 8.4 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 50 पैसे के सुधार के साथ 118.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 330 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 25 पैसे की नरमी के साथ 25.5 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 125000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 6 रुपये की बढ़त के साथ 342 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 290.5 रुपये की गिरावट के साथ 2847.5 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1150 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 28 पैसे के सुधार के साथ 10.89 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 24 पैसे की नरमी के साथ 7.79 रुपये हुआ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में विकास, विश्वास और विजन के साथ नव वर्ष की विकास भरी शुरुआत : वीरमगाम विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास

- वीरमगाम, देत्रोज और मांडल तहसीलों को 497 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात
- कभी संसाधनों की कमी, वर्षा आधारित खेती और रोजगार के लिए युवाओं के पलायन के लिए जाना जाने वाला मांडल, वीरमगाम और बेचराजी क्षेत्र प्रधानमंत्री के विकास विजन से स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन-ऑटो हब बन गया है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

(जीएनएस)। : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वर्ष 2026 के पहले दिन गुरुवार को वीरमगाम विधानसभा क्षेत्र के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और ओवरब्रिज सहित 497 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि कभी संसाधनों की कमी, वर्षा आधारित खेती और रोजगार के लिए युवाओं के पलायन जैसी विकट स्थिति से जूझता मांडल, बेचराजी और वीरमगाम क्षेत्र आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकास विजन से स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एसआईआर) और ऑटो हब बन गया है।

इस संदर्भ में श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने अंतिम व्यक्ति के हित के संकल्प और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र से विकास की चरम सीमा का उदाहरण पेश किया है।

उन्होंने कहा कि विकास की राजनीति का जो दृष्टिकोण प्रधानमंत्री ने अपनाया है, उसे अब सभी ने स्वीकार कर लिया है और बिहार के हाल ही में हुए चुनाव के परिणाम इसका आदर्श उदाहरण हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात में पिछले ढाई दशक से अधिक समय से श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी सहित जो विकास कार्य डबल इंजन सरकार की गति से हुए हैं, उससे गुजरात देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए वीरमगाम-मांडल क्षेत्र में रोड और रेलवे सहित अनेक कार्य हुए हैं। पिछले तीन वर्षों में ही मांडल-बेचराजी एसआईआर को जोड़ने वाली सड़कों और पुलों के 488 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हुए हैं। एसआईआर से जुड़ने वाले हाईवे, परिवहन में बुनियादी ढांचे के विकास और फोरलेन रोड तथा रेलवे ओवरब्रिज के कारण इस क्षेत्र के विकास को नई दिशा और नई गति

मिलेगी। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होने से कोकता फाटक पर वर्षो से चली आ रही ट्रैफिक की समस्या खत्म होगी, जिससे लगभग 1 लाख नागरिकों के समय और ईंधन की बचत होगी।

देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी परियोजनाओं की गति की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विभिन्न एक्सप्रेस-वे, कॉरिडोर और रणनीतिक पुलों एवं सुरंगों के कार्य पूरे किए गए हैं। जहां 2014 से पहले रोजाना 12 किमी नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाता था, वहीं आज रोजाना 34 किमी नेशनल हाईवे बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने भी नमो शक्ति एक्सप्रेस-वे और 1155 किमी के 12 गरवी गुजरात हाईस्पीड कॉरिडोर के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नागरिकों से अपील की कि जब इतने बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हो रहा हो, तब हमें भी स्वच्छता पर विशेष जोर देना चाहिए और स्वच्छता लोगों का सहज स्वभाव बनना चाहिए।

इस अवसर पर वीरमगाम के विधायक श्री हार्दिक पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास किया है, जिनका लाभ स्थानीय क्षेत्र सहित शंखेश्वर और बेचराजी के श्रद्धालुओं को मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछले तीन वर्षों में वीरमगाम विधानसभा क्षेत्र को 2500 करोड़ रुपए से अधिक विकास के कार्य मिले हैं।

विधायक श्री पटेल ने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार द्वारा इस बात की चिंता की गई है कि विकास से कोई भी वंचित न रह जाए। इस मौके पर सुपोषित गुजरात अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेट बास्केट वितरित किए। सड़क एवं भवन विभाग के मुख्य अभियंता ने स्वागत भाषण दिया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वीरमगाम विधानसभा क्षेत्र की जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया उनमें वीरमगाम नगर पालिका से मांडल-दसाड़ा रोड का 285 करोड़ रुपए का कार्य, वीरमगाम शहर के रैयापुर ओवरब्रिज का 91 करोड़ रुपए का कार्य, मांडल तहसील के विठ्ठलापुर से देत्रोज-कड़ी रोड के रिसर्फेसिंग का 55 करोड़ रुपए का कार्य, वीरमगाम तहसील के थोरी मुबारक से लीया-वांसवा रोड का 39 करोड़ रुपए का कार्य, करकथल-हांसलपुर रोड का 12 करोड़ रुपए का कार्य, देत्रोज नए सर्किट हाउस का 5 करोड़ रुपए का कार्य, वीरमगाम नए सर्किट हाउस का 5 करोड़ रुपए कार्य, देत्रोज सब रजिस्ट्रार कार्यालय का 2.45 करोड़ रुपए का कार्य तथा वीरमगाम तहसील के सचाणा बाइपास रोड के 3 करोड़ रुपए के कार्य सहित विभिन्न विकास कार्य शामिल हैं।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कंचनबा वाघेला, जिला कलेक्टर श्री सुजीत कुमार, जिला विकास अधिकारी श्री विदेह खरे, जिला पुलिस अधीक्षक श्री ओम प्रकाश जाट, अग्रणी श्री शैलेषभाई दावड़ा, सड़क एवं भवन विभाग के मुख्य अभियंता एवं विशेष सचिव श्री जे.ए. गांधी, तहसील पंचायतों के अध्यक्ष, वीरमगाम नगर पालिका अध्यक्ष, पालिका एवं तहसील पंचायत के सदस्य, पूर्व विधायक और सामाजिक एवं राजनीतिक अग्रणियों सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

प्लेन उड़ाने से पहले एअर इंडिया पायलट ने शराब पी, ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट में फेल

(जीएनएस)। वैंकूवर। अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मानकों को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। कनाडा के वैंकूवर से दिल्ली आने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट AI186 को उस समय दो घंटे की देरी का सामना करना पड़ा, जब टेक-ऑफ से ठीक पहले विमान के पायलट पर शराब पीने का आरोप लगा। सुरक्षा नियमों के तहत तत्काल कार्रवाई करते हुए पायलट को फ्लाइट से उतार दिया गया और उसकी जगह दूसरे पायलट को जिम्मेदारी सौंपी गई।

घटना 23 दिसंबर की है। जानकारी के मुताबिक, एअर इंडिया की फ्लाइट AI186 वैंकूवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। इसी दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद एक स्टाफ सदस्य ने कथित तौर पर पायलट को वाइन पीते हुए देखा। स्टाफ ने तुरंत इस बात की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी, जिसके बाद कनाडाई एविएशन अथॉरिटी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पायलट से पूछताछ की।

जांच के दौरान अधिकारियों को पायलट के मुंह से शराब की गंध महसूस हुई। इसके बाद नियमों के अनुसार उसका ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट कराया गया, जिसमें पायलट असफल पाया गया। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में पायलटों के लिए "ज़ीरो टॉलरेंस" नीति लागू होती है, जिसके तहत ड्यूटी से पहले या ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार का अल्कोहल सेवन सख्त अपराध माना जाता है। इसी के चलते पायलट को तुरंत फ्लाइट से हटा दिया गया।

सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत एअर इंडिया ने बिना कोई जोखिम लिए वैकल्पिक पायलट को रोस्टर में शामिल किया।

सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद फ्लाइट को रवाना किया गया, लेकिन इस बदलाव और औपचारिकताओं के कारण विमान करीब दो घंटे की देरी से दिल्ली के लिए उड़ान भर सका। इस दौरान यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। एअर इंडिया के प्रवक्ता ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा एयरलाइन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रवक्ता के अनुसार, "सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए संबंधित पायलट को फ्लाइट ड्यूटी से हटा दिया गया और दूसरे पायलट को जिम्मेदारी सौंपी गई। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हम खेद प्रकट करते हैं और स्थानीय अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग कर रहे हैं।"

एयरलाइन की ओर से यह भी बताया गया कि इंतजार के दौरान यात्रियों के लिए नाश्ते और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई, ताकि उन्हें अधिक परेशानी न हो। साथ ही यात्रियों को आश्वस्त किया गया कि सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

इस घटना के बाद संबंधित पायलट के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने तक उसे ड्यूटी से हटा दिया गया है। विमानन नियमों के तहत दोषी पाए जाने पर पायलट का लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है, साथ ही कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी संभव है।

यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कितना जरूरी है। एअर इंडिया और कनाडाई अधिकारियों की तत्परता से जहां संभावित खतरे को समय रहते टाल लिया गया, वहीं यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों के प्रति 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति का कड़ाई से पालन भी किया गया।

पीएनजी ज्वेलर्स ने लाइटस्टाइल बाय पीएनजी के साथ विकास के अगले पड़ाव को गति दी, सारा तेंदुलकर को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया

(जीएनएस)। पुणेः पीएनजी ज्वेलर्स के समकालीन हल्के वजन वाले उत्तम आभूषण ब्रांड लाइटस्टाइल बाय पीएनजी ने सारा तेंदुलकर को अपना ब्रांड एंबेसडर घोषित किया है. यह कदम भारत के भविष्य के ज्वेलरी उपभोक्ताओं से ब्रांड के जुड़ाव को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

यह साझेदारी पीएनजी ज्वेलर्स के पुराने ग्राहकों और भविष्य के ग्राहकों के बीच एक धोरणात्मक सेतु के रूप में लाइटस्टाइल की भूमिका को और मजबूत करती है. पीएनजी ज्वेलर्स लगभग दो सदियों से पीढ़ियों से एक विश्वसनीय नाम रहा है, वहीं लाइटस्टाइल को विशेष रूप से आधुनिक रिटेल प्रारूप, समकालीन डिजाइन भाषा और एक सर्वव्यापी अनुभव के माध्यम से अगली पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बने रहने के लिए सोच-समझकर तैयार किया गया है.

लाइटस्टाइल के पीछे की व्यापक सोच के बारे में बात करते हुए, पीएनजी ज्वेलर्स के अध्यक्ष और व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. सौरभ गाडगीळ ने कहा, "लाइफस्टाइल बाय पीएनजी हमारे मौजूदा ग्राहकों और भविष्य के ग्राहकों के जोड़ने का एक अच्छा और दीर्घकालिक प्रयास है. पीएनजी ने पीढ़ियों से विश्वास संपादन किया है, लेकिन हमारे लिए यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम आज के युवा उपभोक्ताओं की सोच, खरीदारी और अभिव्यक्ति के तरीके के अनुरूप बने रहें. लाइफस्टाइल को एक आधुनिक रिटेल फॉर्मेट के रूप में बनाया गया है, जिसमें मजबूत ओमनीचैनल उपस्थिति है और इसे केवल पारंपरिक अवसरों तक सीमित न रखकर रोज के पलों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया

गया है. यह कोई शार्ट टर्म स्टाइल पहल नहीं है, बल्कि पीएनजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र है, जिसमें मर्चेंडाइजिंग, प्लानिंग, मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विशेष ध्यान दिया गया है. हमारे पायलट स्टोर्स को मिली उत्साहजनक प्रतिसाद ने हमें प्रमुख बाजारों में ब्रांड को संरचित तरीके से विस्तार करने का आत्मविश्वास दिया है."

सारा तेंदुलकर की स्वाभाविक शालीनता, आधुनिक दृष्टिकोण और मजबूत डिजिटल जुड़ाव उन्हें ब्रांड की विचारधारा के लिए एकदम उपयुक्त बनाते हैं. इंस्टाग्राम पर 8.9 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ, उन्हें उनकी आकर्षक स्टाइल, प्रामाणिकता और संतुलित व्यक्तित्व के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है. उत्कृष्ट डिझाइन, सादगीपूर्ण और आराम को प्राथमिकता देने वाले फैशन के प्रति उनकी पसंद, लाइटस्टाइल के डिजाइन सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से मेल खाती है.

इस साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए सारा तेंदुलकर ने कहा, "लाइटस्टाइल सहजता और व्यक्तित्व की भावना को दर्शाता है, जो मुझे बहुत स्वाभाविक लगता है. इसकी ज्वेलरी हल्की, सोच-समझकर डिज़ाइन की गई है और रोज़ की ज़िंदगी के लिए उपयुक्त है, जिससे यह साझेदारी मेरे लिए वास्तव में रोमांचक बन जाती है."

इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, लाइटस्टाइल बाय पीएनजी के मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्रमुख हेमंत चव्हाण ने कहा, "सारा उन युवा महिला की सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनके लिए लाइटस्टाइल बनाया गया है - आत्मविश्वास से भरपूर, आधुनिक और अपने तरीके से अभिव्यक्त. युवा दर्शकों के साथ सहजता से जुड़ने की उनकी क्षमता, लाइटस्टाइल की उस महत्वाकांक्षा को मजबूत करती है कि वह भविष्य के उन उपभोक्ताओं के लिए पसंदीदा ज्वेलरी डेस्टिनेशन बने जो डिज़ाइन, सहजता और प्रामाणिकता को महत्व देते हैं".

ब्रांड एंबेसडर के रूप में, सारा तेंदुलकर ब्रांड और कलेक्शन अभियानों में नज़र आएंगी, डिजिटल पहलों, मीडिया इंटरैक्शन में भाग लेंगी और प्रमुख स्टोर लॉन्च में शामिल होंगी. इसके अलावा वह चुनिंदा कलेक्शन के लिए स्टाइल म्यूज़ के रूप में भी काम करेंगी. दो साल की यह साझेदारी दिसंबर 2025 में शुरू होगी, और सारा के साथ डिज़ाइन किए गए कलेक्शन मार्च 2026 से लॉन्च किए जाने की योजना है.

लाइफस्टाइल बाय पीएनजी एक स्वतंत्र बिज़नेस वर्टिकल के रूप में काम करता है, जो उन महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो पारंपरिक या त्योहारों के अलावा भी आभूषण खरीदती हैं, चाहे वह स्वयं के लिए हो, गिफ्टिंग हो या रोज के पलों के लिए. यह ब्रांड एक सशक्त ओमनीचैनल दृष्टिकोण अपनाता है जो भौतिक स्टोर, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कंटेंट आधारित एंगेजमेंट को एकीकृत करता है.

पुणे और गोवा में पायलट स्टोरों से मिली उत्साहजनक प्रतिसाद के बाद, लाइटस्टाइल अब सुनियोजित विस्तार के लिए तैयार है. ब्रांड का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 तक लगभग 50 स्टोर्स तक विस्तार करना है, जिसमें कंपनी के स्वामित्व और फ्रेंचाइजी के दोनों प्रारूप शामिल होंगे, साथ ही एक ऑनलाइन स्टोर और ऐप भी होगा. विस्तार का प्रारंभिक चरण महाराष्ट्र पर केंद्रित होगा, जिसके बाद भारत के अन्य हिस्सों में विस्तार किया जाएगा.

पश्चिम रेलवे के निर्माण विभाग अहमदाबाद में खेमराज मीना ने जनसंपर्क अधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के निर्माण विभाग, अहमदाबाद में दिनांक 01 जनवरी 2026 को श्री खेमराज मीना ने जनसंपर्क अधिकारी (PRO) के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व खेमराज मीना पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इंदौर में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

इससे पूर्व मीना पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल तथा दक्षिण रेलवे के तिरुवनंतपुरम मंडल में भी जनसंपर्क अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएँ दे चुके हैं।

शैक्षणिक योग्यता के रूप में खेमराज मीना ने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है। उनके अनुभव एवं कार्यकुशलता से पश्चिम रेलवे के निर्माण विभाग के जनसंपर्क कार्यों को नई दिशा मिलेगी।

पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें वसई रोड स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट/शॉर्ट ओरिजिनेट होंगी

महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन हेतु कुछ ट्रेनों के लिए अस्थायी परिवर्तन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा बोरीवली–कांदिवली के बीच 5वीं एवं 6वीं रेलवे लाइन के निर्माण कार्य से संबंधित आवश्यक नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) कार्य को सुचारु रूप से संपन्न करने हेतु कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं के अस्थायी नियमन की योजना बनाई गई है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दो मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें - ट्रेन संख्या 19426 नंदुरबार–बोरीवली एक्सप्रेस तथा ट्रेन संख्या 19418 अहमदाबाद–बोरीवली एक्सप्रेस को 17 जनवरी, 2026 तक वसई रोड स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा।

इसी प्रकार, दो मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें - ट्रेन संख्या 19425 बोरीवली–नंदुरबार एक्सप्रेस तथा ट्रेन संख्या 19417 बोरीवली–अहमदाबाद एक्सप्रेस को 18 जनवरी, 2026 तक वसई रोड स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन अधीक्षकों के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखें तथा उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएँ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मांडल के खंभलाय माताजी मंदिर में दर्शन-पूजन कर धन्यता का अनुभव किया

(जीएनएस)। गांधीनगर : नव वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को मांडल तहसील में स्थित खंभलाय माताजी मंदिर में विधिवत रूप से दर्शन कर पूजा-अर्चना की।

इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र सहित राज्य की सुख-समृद्धि, शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना की और आत्मिक धन्यता का अनुभव किया। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिभाव एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो उठा।

उल्लेखनीय है कि खंभलाय माताजी मंदिर भक्ति, विश्वास और परंपरा के प्रतीक के साथ ही जनमानस की आस्था से जुड़ा हुआ शक्ति साधना का एक पवित्र स्थान है।

दर्शन-पूजन के दौरान विधायक श्री हार्दिक पटेल सहित मंदिर के न्यासीगण, स्थानीय अग्रणी और भक्तजन उपस्थित रहे।

भारतीय रेल का राष्ट्र को नव वर्ष का उपहार: गुवाहाटी और हावड़ा के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

(जीएनएस)। रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली के रेल भवन में आयोजित बैठक में नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए घोषणा की कि असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का संचालन शुरू होगा। उन्होंने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का संपूर्ण परीक्षण, जांच और प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। जनवरी माह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस मार्ग पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय रेल, राष्ट्र और इसके रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने यह भी बताया कि 2026 में कई यात्री-केंद्रित पहल शुरू की जाएंगी और यह भारतीय रेल के लिए बड़े सुधारों वाला वर्ष होगा।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से असम राज्य के कामरूप महानगरपालिका और बोंगाई गांव और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, पूर्वी बर्धमान, हुगली और हावड़ा जैसे जिलों को लाभ मिलेगा। ट्रेन में 16 कोच होंगे, इनमें 11 थ्री-टियर एसी कोच, 4 टू-टियर एसी कोच और 1 फर्स्ट-क्लास एसी कोच शामिल हैं। इसकी कुल क्षमता लगभग 823 यात्रियों की होगी।

श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूरी तरह से नए सस्पेंशन वाली एक नई बोगी विकसित की गई है। डिजाइन के मानकों को नए स्तर पर ले जाया गया है। इसके आंतरिक भाग और सीढ़ियां एर्गोनॉमिक डिजाइन पर आधारित हैं, और सुरक्षा के लिए विशेष मापदंड लागू किए गए हैं।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रात्रिकालीन यात्राओं के लिए आरामदायक, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता का अनुभव प्रदान करेगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की समय सारिणी इस प्रकार बनाई गई है कि यह शाम को अपने प्रस्थान स्थल से रवाना होकर अगली सुबह अपने गंतव्य पर पहुंचेगी।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों को क्षेत्र विशेष व्यंजनों का आनंद मिलेगा। गुवाहाटी से शुरू होने वाली ट्रेन में प्रामाणिक असमिया व्यंजन परोसे जाएंगे, जबकि कोलकाता से शुरू होने वाली ट्रेन में पारंपरिक बंगाली व्यंजन परोसे जाएंगे। इससे रेल में आनंददायक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भोजन मिलना सुनिश्चित होगा।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की विशेषताएं:

- 180 किमी प्रति घंटे तक की गति वाली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन
- बेहतर तकिए के साथ एर्गोनॉमिक (ऐसे उत्पाद, जो आरामदायक, सुरक्षित और कुशल हों) रूप से डिज़ाइन किए गए बर्थ
- सुगम आवागमन के लिए प्रवेश द्वारों सहित स्वचालित दरवाजे
- बेहतर सस्पेंशन और शोर कम करने की क्षमता के साथ बेहतर यात्रा का आनंद लें।

कवच से सुसज्जित

- उच्च स्वच्छता बनाए रखने के लिए कीटाणुनाशक तकनीक
- उन्नत नियंत्रण और सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित ड्राइवर केबिन
- वायुगतिकीय बाहरी बनावट और स्वचालित बाहरी यात्री दरवाजे

दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था

- आपातकालीन स्थिति में यात्री और ट्रेन प्रबंधक/लोको पायलट के बीच संचार के लिए आपातकालीन टॉक-बैक यूनिट।
- सभी कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।
- विद्युत कैबिनेट और शौचालयों में एरोसोल आधारित अग्नि पहचान और शमन प्रणाली से अग्नि सुरक्षा में सुधार हुआ है।
- पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भारतीय रेल के एक नए युग की शुरुआत है। यह रात भर की यात्रा के लिए गति, आराम और आधुनिक सुविधाओं का संगम है। यह भारतीय रेल की यात्री-केंद्रित सेवाओं, तकनीकी नवाचार और क्षेत्रीय संपर्क पर केंद्रित प्रतिबद्धता को दर्शाती है और यात्रियों को एक सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध यात्रा प्रदान करती है।

रेलवन ऐप से अनारक्षित टिकट बुकिंग पर यात्रियों को मिलेगा 3% का सीधा लाभ

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में रेलवे बोर्ड की महत्वपूर्ण पहल

रेल यात्रियों को डिजिटल भुगतान के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुकिंग के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवन (RailOne) ऐप पर अनारक्षित टिकट बुकिंग पर 3 प्रतिशत लाभ प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

वर्तमान में रेलवन ऐप पर आर-वॉलेट (R-Wallet) के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को 3 प्रतिशत बोनस कैशबैक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा को और अधिक व्यापक बनाते हुए रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि अब आर-वॉलेट के अतिरिक्त सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों—जैसे यूपीआई, डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदि—से रेलवन ऐप पर अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को टिकट मूल्य पर 3 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि, आर-वॉलेट के माध्यम से टिकट बुकिंग की स्थिति में पूर्व की भांति 3 प्रतिशत बोनस कैशबैक की सुविधा जारी रहेगी।

रेलवे बोर्ड द्वारा घोषित यह 3 प्रतिशत छूट/लाभ योजना 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान योजना के प्रभाव का फीडबैक के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा तथा आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

रेलवे बोर्ड की यह पहल यात्रियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी तथा अनारक्षित टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को और अधिक सरल, तेज, सुविधाजनक एवं पारदर्शी बनाएगी। डिजिटल माध्यमों से टिकट बुकिंग करने पर यात्रियों को न केवल समय की बचत होगी, बल्कि उन्हें प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा।